

24 April The Hindu In an Oil Sick

तेल का संकट

- पृष्ठभूमि** - अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को समाप्त कर दिया। जुलाई 2015 में ईरान और सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के बीच यह समझौता हुआ था। कि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रमों पर रोक लगाएगा, और इसके बाद उस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। यह समझौता बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए समझौते को समाप्त किया था तथा ईरान द्वारा किये जा रहे यूरेनियम संवर्धन के प्रयासों को हतोत्साहित करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
- ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए ट्रंप ने पहला कदम उसका तेल निर्यात बंद करवाने के लिए उठाया, तथा भारत सहित कई देशों को ईरान से तेल निर्यात रोकने हेतु 6 माह की समय सीमा निर्धारित कर दी।

संदर्भ

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने पर भारत समेत आठ देशों की दी गई छूट आगे न बढ़ाने का फैसला किया है।
- अमेरिका ने 180 दिनों की ये छूट भारत, चीन, इटली, ग्रीस, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और तुर्की को दी थी लेकिन इसकी समय सीमा 2 मई को खत्म हो रही है।
- ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है।
- इसके बाद भारत ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदा पाएगा। अगर फिर भी भारत ऐसा करता है तो अमेरिका के साथ उसके रिश्ते खराब होंगे।
- ये भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा इससे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे और मंहगाई भी बढ़ेगी, भारत को दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना होगा, इससे आयात बिल बढ़ेगा और राजकोषीय संतुलन बिगड़ेगा भारतीय रुपये की क्रय क्षमता भी प्रभावित होगी।
- तेल का यह संकट, अमेरिका की रणनीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन आपूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- अमेरिका की इस पाबंदी का भारत के बाजार पर क्या असर होगा, इसे लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।
- भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, इस फैसले के असर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अपने ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हितों की रक्षा के लिए अमेरिका समेत अपने सहयोगी देशों के साथ काम करती रहेगी।
- सरकार भारतीय रिफाइनरीज को कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी योजना के साथ तैयार है साथ ही दूसरे तेल उत्पादक देशों से भी बड़े स्तर पर आपूर्ति की जाएगी ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की मांग को पूरा किया जा सके।
- भारत ईरान के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीददार है और सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि उसे भुगतान यूरो व रुपये में करता है।
- भारत के कुल आयात में ईरान और वेनेजुएला का हिस्सा लगभग 18 फीसद है, हालांकि भारत इस कमी की पूर्ति सऊदी अरब, ईराक, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया से आयात बढ़ाकर कर सकता है।
- 2017-2018 में भारत ने अपनी जरूरत का 83 फीसद तेल बाहर से आयात किया।
- भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना का सबसे बड़ा रणनीतिक भागीदार हैं। ऐसे में जरूरत पूरी करने

के लिए अतिरिक्त तेल खरीद की व्यवस्था करना तथा अमेरिका के साथ संबंध भी सामान्य रखना भारत के लिए चुनौती साबित होगी।

नकारात्मक प्रभाव

- क्या यह समस्या सिर्फ तेल उत्पादों की आपूर्ति तक ही सीमित है?
- ऑब्ज़र्वर रिज़र्व फाउंडेशन के अनुसार भारत किसी तरह तेल की आपूर्ति तो कर लेगा, लेकिन मंहगाई बढ़ने का संकट जरूर हो सकता है।
- “ईरान से आने वाले तेल में कमी तो जरूर आएगी, लेकिन तेल की आपूर्ति कहीं से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि तेल की कमी होने वाली है, बल्कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी और रुपये की कीमत घटेगी। एक बड़े देश का उत्पादन बाजार से बाहर हो जाता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं अगर वो उत्पादन दूसरी जगहों से पूरा हो सकता है अगर सऊदी अरब अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे-तो कीमतें फिर कम हो जाएंगी।”

ईरान से व्यापार पर असर?

- भारत का पक्ष है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों और निर्णयों के लिए प्रतिबंध है, परंतु व्यापारिक जटिलताओं और अमेरिकी डॉलर में हो रहे वैश्विक व्यापार के पक्ष को ध्यान में रखते हुए अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा रहा है। जहां तक ईरान से व्यापार का सवाल है जहां तक व्यापार संभव है, भारत करता रहेगा।”
- अमेरिका फैसले के बाद ईरान को धन के भुगतान में मुश्किलें आएंगी क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पर अमेरिका का नियंत्रण है दोनों देश व्यापार का कुछ हिस्सा रुपयों में डील करते हैं लेकिन ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है।
- अर्थशास्त्र का सामान्य नियम यही कहता है कि दोनों देश अपना पूरा कारोबार रुपये में तभी कर सकते हैं, जब दोनों के बीच व्यापार-संतुलन हो यानी जितना माल भारत आता हो उतनी ही कीमत का ईरान को जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान, भारत ऐतिहासिक संबंध तथा भू-राजनीतिक महत्त्व इन दोनों राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, इसलिए भारत के लिए ईरान से संबंध बनाए रखना जरूरी है और भारत बनाए रखेगा तेल की इसमें एक छोटी सी भूमिका है, भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित किया है जिससे भारत को यूरोप के बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो सकती है। इसलिए ईरान और भारत के बीच संबंध महत्वपूर्ण है।

भारत की अर्थव्यवस्था पर असर

- अमेरिका के फैसले के बाद अगर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि आती है, तो इसका असर पड़ेगा।
- सबसे पहले रुपये की कीमत गिरेगी उसका प्रभाव तुरंत दिखता है जैसे-जैसे तेल की कीमत गिरती है, वैसे ही राजकोषीय घाटा बढ़ता है रुपये की कीमत जब डॉलर के मुकाबले एक रुपये बढ़ती है तो भारत का राजकोषीय घाटा सीधे 800 करोड़ रुपये बढ़ जाता है।
- इस फैसले से आठ देश प्रभावित होंगे जिनमें जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के मित्र देश भी शामिल हैं।
- जापान और दक्षिण कोरिया ने ईरान से तेल आयात को या तो रोक दिया है, या बिल्कुल कम कर दिया है, लेकिन अमेरिका सरकार के फैसले का असर देशों के संबंधों पर पड़ सकता।
- भारत के लिए तो यह और भी बड़ी समस्या है क्योंकि अमेरिका उस पर वेनेजुएला से भी अपना तेल आयात घटाने का दबाव बना रहा है, लेकिन भारत के ईरान से सांस्कृतिक-राजनीतिक संबंध हैं इसलिए उसके लिए ईरान को घेरने की अमेरिकी रणनीति में शामिल होना मुश्किल होगा।

क्या हैं विकल्प

- मूल समस्या भुगतान की है क्योंकि बैंकिंग प्रणाली पर अमेरिका का नियंत्रण है इससे निपटने के लिए

यूरोपीय संघ ने एक नई संस्था बनाई थी 'इनस्टेक्स' नाम से जिसके तहत यूरोप और ईरान सीधे वित्तीय लेनदेन पर निर्भरता के बिना कारोबार कर सकते थे।

- ऐसे ही प्रयास चीन ने भी किए हैं चीन युआन में कारोबार करता है और कुछ हद तक भारत भी रुपये में व्यापार कर रहा है लेकिन उसकी सीमाएं हैं सभी बैंकिंग चैनल्स पर डॉलर का प्रभुत्व है और इसे तोड़ने की कोशिशें हो रही है लेकिन भारत सरकार की मुश्किल ये है कि उसे इस मुश्किल से उस समय निपटना है जब भारत में चुनाव हो रहे हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न :- अमेरिका ने अपने सामरिक और आर्थिक हितों के लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाया है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के कारण इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर पड़ रहा है उपर्युक्त कथन के संदर्भ में इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इससे निपटने के वैकल्पिक उपायों पर चर्चा करें।



मोस्क्यूरिक्स

- अफ्रीका के मलावी में मलेरिया बीमारी से बचाव अभियान के लिए 'मोस्क्यूरिक्स' उन्नत मलेरिया वैक्सीन का बड़े पैमाने पर पायलट परीक्षण किया जाएगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 3 अफ्रीकी देशों घाना, केन्या और मलावी के चुनिंदा क्षेत्रों में वैक्सीन के इस्तेमाल की जानकारी दी गई।
- मलेरिया बीमारी विश्व में मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 4.3 लाख मौते मलेरिया के कारण होती है, इसके अधिकांश मामले उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में देखे गए।
- इस वैक्सीन का लक्ष्य दो वर्ष से कम आयु के 120,000 बच्चों का टीकाकरण करना और उसके प्रभावों की जांच करना है।
- हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है इसका मुख्य ध्येय मलेरिया के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए मलेरिया ग्रस्त रोगियों की रक्षा करना है

भारत में मलेरिया के मरीजों का औसत

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2001 में भारत में मलेरिया के 20.9 लाख मामले दर्ज किए गए, वहीं वर्ष 2014 में मलेरिया के 11 लाख मामले दर्ज हुए
- संक्रमित मादा एनोफेलीज मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है
- मलेरिया के प्रमुख लक्षणों में मरीज को कंपकंपी के साथ तेज बुखार आता है सिरदर्द, उल्टी और हाथ-पैरों में दर्द के साथ कमजोरी, और पसीना आना शामिल है।

क्या 2030 तक मलेरिया मुक्त हो सकेगा भारत

- भारत में मलेरिया निर्मूलन के लिए ठोस कदम की बात है तो केंद्र सरकार के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक एवं चिकित्सकों ने 2030 तक भारत को पूरी तरह से मलेरिया मुक्त करने की योजना बनाई है लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि मलेरिया की घातकता के लिए जिम्मेदार प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के संक्रमण पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं ऐसे में साल 2030 तक देश को मलेरियामुक्त करने के अभियान में बाधाएं खड़ी हो सकती हैं।

भारतीय चिकित्सकों की उपलब्धियां

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में संपूर्ण विश्व मलेरिया के कुल मामलों में 80 फीसदी केस भारतीय उपमहाद्वीप में और 15 फीसदी अफ्रीकी देशों में पाये गये थे,
- इसके पश्चात् भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया पर काफी शोध किये, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये इसका परिणाम यह निकला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 के रिपोर्ट में भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए बताया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2016 के मुकाबले 2017-2018 में मलेरिया के मामलों में काफी कमी आयी है।